पत्र सूचना शाखा
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0

प्रदेश सरकार का एक वर्ष का कार्यकाल पूरा
सरकार ने एक साल में जो काम किया है वह स्वागत योग्य है - राज्यपाल
नौजवानों और बेरोजगारों के लिए सरकारी पदों पर चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने जा रही है सरकार - मुख्यमंत्री

लखनऊः 19 मार्च, 2018

उत्तर प्रदेश सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर लोकभवन में 'एक साल नई मिसाल' कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक थे तथा अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। इस अवसर पर विधान सभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित, उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य एवं डाॅ0 दिनेश शर्मा, सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डाॅ0 महेन्द्र नाथ पाण्डेय, राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्यगण, सांसद एवं विधायकगण, मुख्य सचिव श्री राजीव कुमार, पुलिस महानिदेशक श्री ओ0पी0 सिंह सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारीगण उपस्थित थे। कार्यक्रम में भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के लिए एंटी करप्शन ई पोर्टल भी लांच किया गया।
राज्यपाल ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि लोकतंत्र में राज्यपाल और सरकार का अत्यंत महत्वपूर्ण दायित्व होता है। सरकार किसी राजनैतिक दल की हो मगर राज्यपाल की सरकार कही जाती है। राज्यपाल का काम मार्गदर्शन करने का है और वे आवश्यकतानुसार मार्गदर्शन व सलाह देते रहते हैं। 'मेरे रिश्ते पहली सरकार से भी अच्छे थे और आज की सरकार से भी अच्छे हैं। मुझे इस बात का समाधान है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरी सलाह पर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अमर अजर उद्घोष के 101 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य आयोजन किया तथा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित भी किया।' उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी प्रकार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन किया तथा इस अवसर पर अनेक योजनाओं का शुभारम्भ करके प्रदेश को नई पहचान दी। श्री नाईक ने कहा कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश की खस्ता हालत में भी यू0पी0 इंवेस्टर्स समिट का सफल आयोजन करके हिम्मत दिखाने का काम किया है। बिजली, कानून व्यवस्था आदि मोर्चे पर सरकार के ठोस कदम को देखकर उद्योगपतियों का विश्वास देखने को मिला, जिसका परिणाम है कि समिट में 4.68 लाख करोड़ रूपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से बड़ा प्रदेश है और उपभोक्ता भी अधिक संख्या में हैं। समिट में हस्ताक्षर किए गए एम0ओ0यू0 के आधार पर प्रदेश को निश्चित रूप से विकास का नया वातावरण प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को 'उत्तम प्रदेश' बनाना होगा। राज्यपाल ने 'चरैवेति! चरैवेति!!' के शाश्वत संदेश को उद्धृत करते हुए कहा कि निरंतर चलते रहने वाले का भाग्य भी आगे चलता है। इसलिए सब मिलकर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ायें।
राज्यपाल ने मुख्यमंत्री, मंत्रिमण्डल के सदस्यों एवं प्रदेश की जनता को सरकार के एक वर्ष पूरे होने पर बधाई देते हुए कहा कि सरकार ने एक साल में जो काम किया है वह स्वागत योग्य है। मुख्यमंत्री ने इससे पूर्व सरकार के 100 दिन एवं 6 माह पूर्ण होने पर अपनी रिपोर्ट जारी की थी, वह सराहनीय है। जनादेश देने वाली जनता के प्रति जवाबदेही और पारदर्शिता के परिप्रेक्ष्य में रिपोर्ट का जारी होना महत्वपूर्ण है। गत 40 वर्षों से तीन बार विधायक और पांच बार सांसद रहते हुए तथा राजभवन में भी राज्यपाल की हैसियत से वे हर वर्ष अपना कार्यवृत्त प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने कहा कि वास्तव में एक साल का कार्यकाल पूरा होना सिंहावलोकन का अवसर होता है। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि जनता के प्रति जवाबदेही का स्थान सदन है पर वहाँ विकास पर चर्चा नहीं हो पाती है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार प्रदेश में नौजवानों और बेरोजगारों के लिए शीघ्र ही 64 विभागों में लगभग 4 लाख सरकारी पदों पर चयन की प्रक्रिया प्रारम्भ करने जा रही है। चयन प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जाएगी। नये वित्तीय वर्ष में दूसरे राज्यों से जुड़े 54 मार्गों के सौन्दर्यीकरण और उनसे जुड़े मार्गों के लिए 1,333 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। बेहतर यातायात के लिए 33 हजार करोड़ रूपये की लागत से मेरठ, आगरा व कानपुर में मेट्रो रेल की योजना लाई जाएगी। महिलाओं की सुविधा के लिए पचास पिंक बसों की सेवा प्रारम्भ होगी जिनमें से 10 बसों में ड्राईवर और कंडक्टर भी महिला होंगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरूस्त करने व नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए व्यापक कदम उठाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुरूप किसानों की आय दोगुना करने के लिए राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता इसी दृष्टि से सरकार ने एक साल के कार्यकाल में ऋण माफी, गेहूँ व धान क्रय, गन्ना मूल्य भुगतान आदि पर विशेष ध्यान दिया है। राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को वर्ष 2022 तक पक्का आवास उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयास कर रही है। वर्ष 2017-18 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 8 लाख से अधिक आवास स्वीकृत करते हुए 6 लाख आवास पूर्ण किए जा चुके हैं तथा वित्तीय वर्ष के अंत तक शेष आवास भी पूर्ण हो जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष अभियान चलाकर सरकार ने 1 लाख 7 हजार किलोमीटर सड़क को गढ्डा मुक्त करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के सभी जनपदों को समान बिजली आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सरकार द्वारा 57 हजार से अधिक मजरों को विद्युतीकरण करते हुए सौभाग्य (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) के अंतर्गत 32 लाख से अधिक गरीब परिवारों को निशुल्क विद्युत कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। पारम्परिक शिल्प एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 'एक जनपद एक योजना' प्रारम्भ की गई है। उन्होंने कहा कि साधारण मिट्टी के प्रयोग में आम लोगों को आ रही दिक्कतों को देखते हुए राज्य सरकार ने राॅयल्टी समाप्त करने का निर्णय किया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि ईंट भट्ठा मालिक ईंट के दाम कम करेंगे तो भट्ठों को भी मिट्टी की राॅयल्टी माफ कर दी जाएगी।

कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वागत उद्बोधन दिया तथा उप मुख्यमंत्री ने धन्यवाद ज्ञापित किया। इस अवसर पर लोक कलाकारों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस अवसर पर सूचना विभाग द्वारा तैयार की गई पुस्तिका 'एक साल एक मिसाल' का विमोचन किया गया तथा पुलिस विभाग द्वारा तैयार की गई डाक्यूमेंटरी का भी प्रदर्शन किया गया।

अंजुम/ललित/राजभवन (111/27)